Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-16, अंक-17 01-15 सितंबर, 2021 (पाक्षिक) ₹20

'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास'

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' फहराते
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित
'ओबीसी समुदाय के केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान समारोह' में
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी
वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की बैठक को संबोधित करते
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में तैनात सशस्त्र बलों के लिए 'ट्रॉमा केयर
एम्बुलेंस' की खेप को झंडी दिखाकर रवाना करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है: नरेन्द्र मोदी

लाल किले की प्राचीर से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, ''यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ़ देश की...

14 समुद्री विवादों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस...

17 ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 नए केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 अगस्त...

19 उज्ज्वला योजना से बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के संकल्प को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत 10 अगस्त को महोबा, उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग...

31 आज देशभर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अगस्त को 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद'' में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से...

वैचारिकी

समाज और विचारधारा / **दीनदयाल उपाध्याय** 22

श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं रहे 24

साक्षात्कार

मोदी सरकार समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है: **के. लक्ष्मण** 32

लेख

टीकाकरण का नया इतिहास / **जगत प्रकाश नड्डा** 28

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान:
एक अनुकरणीय पहल / **शिवप्रकाश** 30

अन्य

14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा: नरेन्द्र मोदी 12

प्रधानमंत्री ने 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए विश्व नेताओं का आभार प्रकट किया 13

कांग्रेस सरकार में हर रक्षा सौदे में घोटाले हुए: जगत प्रकाश नड्डा 15

महिला मोर्चा ने 75 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया 18

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–पाम ऑयल के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी 20

मानसून सत्र के दौरान संसद ने पारित किए 22 विधेयक 21

वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ 26

सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूलभाव है– सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वास्तव में यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना की ही अभिव्यक्ति है।

जगत प्रकाश नड्डा

नेतृत्व के बदलने से क्या फर्क पड़ता है इसे भी हमें समझना चाहिए। 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,43,000 करोड़ रुपये था। 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ रुपये है। 1,35,000 करोड़ रुपये से सिर्फ नए असलहे खरीदने की व्यवस्था की गई है।

अमित शाह

पहले की सरकारों ने दशकों तक जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विकास से वंचित रख सिर्फ अपने परिवारों की चिंता की। मोदीजी ने यहां विकास के नये युग की शुरुआत कर गरीब नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ा। उसी का परिणाम है कि आज जम्मू-कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

राजनाथ सिंह

'भारत छोड़ो आंदोलन' की वर्षगांठ के अवसर पर मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण एवं नमन करता हूं। उनके संघर्ष की कहानियां आज भी जनमानस के हृदयपटल पर अंकित हैं। देश को दासता से मुक्ति दिलाने वाले इन सच्चे सपूतों के प्रति पुनः कोटि कोटि नमन!

बी.एल. संतोष

भारत के 'लिबरल', उनके समर्थक, सेकुलरवादी एक विशेष वर्ग हैं, जिनके लिए हिंसा, हवाई अड्डे पर तबाही, हवाई जहाज से चिपके और मरते हुए लोग, जलते हुए पुस्तकालय, अफगानिस्तान में संविधान नहीं बल्कि शरीयत का शासन कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए केवल तालिबान की प्रेस कांफ्रेंस ही एक उपलब्धि है।

नितिन गडकरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय नियोजन के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन – ऑयल पाम को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से तिलहन और पाम ऑयल के बढ़ते क्षेत्र और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे बीज उद्यानों को सहायता मिलेगी और निवेश बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी।

यही समय है... सही समय है

- नरेन्द्र मोदी

यही समय है, सही समय है,
भारत का अनमोल समय है।

असंख्य भुजाओं की शक्ति है,
हर तरफ देश की भक्ति है।

तुम उठो तिरंगा लहरा दो,
भारत के भाग्य को फहरा दो।

कुछ ऐसा नहीं, जो कर न सको,
कुछ ऐसा नहीं, जो पा न सको।

तुम उठ जाओ,
तुम जुट जाओ।

सामर्थ्य को अपने पहचानो,
कर्तव्य को अपने सब जानो।

यही समय है, सही समय है,
भारत का अनमोल समय है।

(15 अगस्त 2021 को लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पढ़ी गई कविता)

संपादकीय

उपलब्धियों से भरी यात्रा प्रारंभ करने का अब सही समय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए आने वाले 25 वर्षों में एक सुदृढ़, समृद्ध एवं भव्य राष्ट्र के निर्माण की रूपरेखा रखी है। आने वाले 25 वर्षों को 'अमृत काल' कहते हुए उन्होंने कहा कि यह अपनी प्रतिभा, संसाधन एवं शक्ति के आधार पर उपलब्धियों से भरी यात्रा प्रारंभ करने का सही समय है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र के साथ 'सबका प्रयास' जोड़ते हुए उन्होंने हर देशवासी को स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूर्ण होने तक एक 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। 'अमृत काल' के लक्ष्यों से समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने, देश में ग्रामीण-शहरी के अंतर को पाटते हुए आधुनिक अवसंरचना से युक्त करने तथा लोगों के जीवन में सरकारी तंत्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को न्यूनतम करने जैसे कदमों के रूप में स्पष्ट किया। नए भारत का उदय हर व्यक्ति की भागीदारी एवं हर भारतीय की लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता एवं समर्पण से निस्संदेह सुनिश्चित होगा।

पिछले सात वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करते हुए अनेक अनुपम उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यह ऐसे ही संकल्प का परिणाम है कि भारत ने अपनी एकजुट शक्ति से न केवल कोविड-19 महामारी का मजबूती से सामना किया, बल्कि दो टीकों का निर्माण कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त कर पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया।

पिछले सात वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करते हुए अनेक अनुपम उपलब्धियां प्राप्त की हैं

जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आने वाले दिनों में 'गति शक्ति' पर बल दिया, वहीं अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत उपलब्धियां प्राप्त करने का लक्ष्य राष्ट्र के सामने रखा। 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' की राष्ट्रीय योजना की घोषणा से देश में व्यापक अवसंरचना का निर्माण तो होगा ही, साथ ही सौ लाख करोड़ रुपये के निवेश से देशभर में व्यापक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जहां देश ने कई क्षेत्रों में शत-प्रतिशत उपलब्धियां अर्जित की हैं, वहीं शत-प्रतिशत गांवों में सड़कें, शत-प्रतिशत परिवारों में जन-धन खाते, शत-प्रतिशत अर्हता प्राप्त परिवारों को आयुष्मान कार्ड एवं गैस कनेक्शन, शत-प्रतिशत लाभार्थियों को पक्का आवास और इसी प्रकार कई अन्य क्षेत्रों में भी शत-प्रतिशत उपलब्धियां प्राप्त करने का लक्ष्य अब देश के सामने है। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए पूरे देश में कई अभिनव योजनाओं के माध्यम से युवा, महिला, गरीब, कमजोर, वंचित एवं शोषित व्यक्तियों का सशक्तिकरण हुआ है तथा लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन संभव हुआ है।

आज जब सारा देश 75 सप्ताह का 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र का संबोधन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति पूरे राष्ट्र की कृतज्ञता अर्पित करते हुए शुरू किया। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को 'विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दरअसल, यह दिन अब तक के मानव इतिहास के सबसे बड़ी विभीषिकाओं में से एक है। 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' भारत-विभाजन में हुए असंख्य जान-माल की हानि एवं लाखों लोगों के अपने घर से उजड़ने की पीड़ा एवं वेदना को याद करेगा। स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद आज जब नयी संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, देश डिजिटल तकनीक, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नये क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। आज भारत आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में ऐतिहासिक निर्णयों जैसे धारा 370 को निरस्त करना, जीएसटी को लागू करना, सीएए एवं तीन तलाक पर कानून बनाना, सुरक्षा बलों के लिए ओआरओपी, श्रीराम मंदिर का निर्माण, सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक जैसे मजबूत निर्णय सफलतापूर्वक ले रहा है। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं करिश्माई नेतृत्व में भारत 'कैन डू (Can Do)' पीढ़ी के युवाओं से युक्त है जो अद्भुत उपलब्धियों एवं सिद्धियों के गीत गा रहे हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि यह 'अमृत काल' देश को अकल्पनीय ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन

यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है: नरेन्द्र मोदी

आने वाले 25 वर्षों को 'भारत के सृजन का अमृत काल' बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को लाल किले की प्राचीर से 100 लाख करोड़ रुपये की 'गतिशक्ति योजना', देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' और अगले 75 सप्ताह में 75 वंदेभारत रेल गाड़ियां चलाने के साथ ही सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोले जाने की घोषणा की

लाल किले की प्राचीर से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, ''यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ़ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो।''

नागरिकों से समय के साथ ख़ुद को बदलने का आग्रह करते हुए श्री मोदी ने यह भरोसा भी जताया कि 21वीं सदी में भारत के सपनों को पूरा होने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबके प्रयास' से इस लक्ष्य को हासिल करना है।

देश के विकास में आधुनिक बुनियादी ढांचा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने वाली होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनायेंगे। श्री मोदी ने भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र और इसका सबसे बड़ा निर्यातक बनाने के मकसद से 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' की स्थापना की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने अगले 75 सप्ताह के भीतर 75 वंदेभारत रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की जो देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी।

साथ ही, आतंकवाद और विस्तारवाद पर उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है और इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़े हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज अपना लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और गगनयान भी बना रहा है और यह स्वदेशी उत्पादन में भारत के सामर्थ्य को उजागर करता है।

हमारी प्राण शक्ति–राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना

श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी

जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है। हमारी प्राण शक्ति– राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना है।

सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देने को लोकतंत्र की असली भावना करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और वहां विधानसभा चुनाव की तैयार चल रही है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 'सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय' लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बनाने जा रहा है।

श्री मोदी ने विश्वास जताया कि हिमालयी, तटीय और आदिवासी क्षेत्र भविष्य में भारत के विकास का 'बड़ा आधार' बनेंगे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत को नयी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के सामर्थ्य का सही और पूरा इस्तेमाल जरूरी है और इसके लिए जो वर्ग या क्षेत्र पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे बढ़ाना ही होगा। श्री मोदी ने कहा कि आज पूर्वोत्तर में संपर्क का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये संपर्क दिलों का भी है और बुनियादी ढांचों का भी है। बहुत जल्द पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जिन जिलों के लिए यह माना गया था कि वह पीछे रह गए, सरकार ने उनकी आकांक्षाओं को जगाया है। उन्होंने कहा कि देश में 110 से अधिक आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें से अनेक जिले आदिवासी अंचल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी अलग-अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है, वह अब पोषणयुक्त चावल देगी। श्री मोदी ने कहा कि राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मध्यान्ह भोजन में मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा।

> 21वीं सदी में भारत के सपनों को पूरा होने से कोई बाधा नहीं रोक सकती

'छोटा किसान, बने देश की शान'

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 'छोटा किसान, बने देश की शान', यह हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उन्होंने कहा कि देश में पहले जो नीतियां बनीं, उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना था, वह नहीं किया गया। अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि देश आज से अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है और यहां से आजादी के 100 वर्षों तक का सफर 'भारत के सृजन का अमृतकाल' है। उन्होंने कहा कि भारत का यह संकल्प सुरक्षित और समृद्ध विश्व की खातिर प्रभावी योगदान के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है, जब वह देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है और खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले देश की आजादी में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज देश उन्हें याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस महामारी में अपनी जान गंवाई, वह भी वंदन के अधिकारी हैं।

टोक्यो ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने अपने मंच से तालियां बजाई और कहा कि यह भारत के खेलों और युवा पीढ़ी का सम्मान है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में अपने सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम पर गर्व है और 54 करोड़ से अधिक लोग पहले ही कोविड-19 के टीके लगवा चुके हैं। श्री मोदी ने देश में टीका निर्माण में शामिल लोगों की भी सराहना की और कहा कि भारत को कोरोना वायरस रोधी टीकों के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं होना पड़ा। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में चिकित्सकों, नर्सों और पराचिकित्सकों के योगदान की भी सराहना की। श्री मोदी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले डिजिटल मंच 'कोविन ऐप' के निर्माण को भी रेखांकित किया।

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन

महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसने दुनिया को हैरान कर दिया है और यह चर्चा का विषय बन गया है। श्री मोदी ने गांवों और शहरों में जीवन के अंतर को पाटने के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के अपने लक्ष्य को पूरा कर लें।

लाल किले पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, विभिन्न दलों के नेता, विदेशी राजनयिक, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के प्रतिनिधियों सहित केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्री मोदी सबसे पहले राजघाट गए और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। यहां से प्रधानमंत्री सीधे लाल किले पहुंचे जहां रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने तिरंगा फहराया और इसके बाद हेलीकॉप्टर से आयोजन स्थल पर पुष्प वर्षा की गई। ■

'हमारी ताकत, हमारी एकजुटता है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी एकजुटता है। हमारी प्राणशक्ति– राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है। नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन की मुख्य बातें:

आजादी का अमृत महोत्सव, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्वभर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

- राष्ट्र पूज्य बापू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे महान क्रांतिवीर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, असम में मातंगिनी हाजरा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबासाहब अम्बेडकर आदि सभी महापुरुषों का ऋणी है।
- कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सिस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाईकर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे हमारे वैज्ञानिक हों आदि सभी वंदन के अधिकारी हैं।
- ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी ने भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। एथलीट्स ने हमारा दिल ही नहीं जीता है, बल्कि भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है।
- अब से हर वर्ष 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में याद किया जाएगा। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना, विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है।
- **वैक्सिनेशन प्रोग्राम–** आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं।
- महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है और यह भी दुनिया के लिए अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है।
- **मृतकों के प्रति संवेदना–** सारे प्रयासों के बाद भी कितने ही लोगों को हम बचा नहीं पाए हैं। कितने ही बच्चों के सिर पर कोई हाथ फेरने वाला चला गया। उसे दुलारने, उसकी जिद्द पूरी करने वाला चला गया। ये असहनीय पीड़ा, ये तकलीफ हमेशा से साथ रहने वाली है।

> 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और अब 'सबका प्रयास' हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बहुत महत्वपूर्ण है

नए भारत के सृजन का अमृत काल

- 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है। नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा जब हम आजादी की शताब्दी मनाएगें, नए भारत के इस सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि, हमें आजादी के सौ वर्ष तक ले जाएगी।
- अमृत काल का लक्ष्य है, भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गावों और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण, जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल न दें। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो।
- अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इतना लम्बा इंतजार भी नहीं करना है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और अब 'सबका प्रयास' हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।
- पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें सैचुरेशन (saturation) तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। शत-प्रतिशत गांवों में सड़कें हों, शत-प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत-प्रतिशत लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो।
- **स्वनिधि योजना–** पटरी और फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वाले, ठेला चलाने वाले साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।
- **जल जीवन मिशन–** मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ दो वर्ष में साढ़े चार करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया है।

- **कुपोषण की समस्या–** गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी को देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग-अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है, उसे fortify करेगी।
- **आरक्षण की नई व्यवस्था–** दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में, ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है।
- आज नार्थ-ईस्ट में 'कनेक्टिविटी' का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नार्थ-ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है।
- 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत आज नार्थ-ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण-पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब नार्थ-ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है।

सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर

- सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही हैं।
- लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बना रही है।
- 'डीप ओसन मिशन' समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने की हमारी महत्वाकांक्षा का परिणाम है। जो खनिज संपदा समंदर में छिपी हुई है, जो तापीय ऊर्जा समंदर के पानी में है, वो देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती है।
- **आकांक्षी जिले–** देश में 110 से अधिक आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें से अनेक जिले हमारे आदिवासी अंचल में हैं।
- **सहकारवाद–** अर्थजगत में भारत सहकारवाद पर बल देता है। सहकारवाद देश के जमीनी स्तर की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम क्षेत्र है। सहकारी एक संस्कार है, सहकारी एक सामूहिक चलने की मनःप्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाए हैं।
- **ग्रामीण भारत–** आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। बीते कुछ वर्ष, गांवों तक सड़क और बिजली की सुविधाओं को पहुंचाने के रहे थे। अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है। गांव में भी डिजिटल उद्यमी तैयार हो रहे हैं।
- **वोकल फॉर लोकल–** सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। आज जब देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ा रहा है तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में और विदेशों में भी लोगों से जोड़ेगा और उनका फलक बहुत विस्तृत होगा।
- **कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की क्षमता–** देश के हर क्षेत्र में हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत सूझ-बूझ से काम कर रहे हैं। हमें अपने कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को शामिल करना होगा। इससे देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।

छोटा किसान बने देश की शान

- छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी।
- देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनीं, उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना था, वो रह गया। अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं।
- **किसान रेल–** आज देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। छोटे किसान, किसान-रेल के जरिए अपने उत्पाद ट्रांसपोर्टेशन के कम खर्च पर दूर-दराज के इलाकों में पहुंचा सकते हैं।
- **स्वामित्व योजना–** गांवों में जमीनों के कागज पर कई-कई पीढ़ियों से कोई काम नहीं हुआ है। खुद जमीन के मालिक होने के बावजूद जमीन पर उनको बैंकों से कोई कर्ज नहीं मिलता है। इस स्थिति को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना कर रही है। गांव-गांव में हर एक घर की, हर जमीन की, ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। इससे ना सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन की व्यवस्था भी कायम हुई है।
- **अगली पीढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर–** हमें मिलकर काम करना होगा, अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हमें मिलकर काम करना होगा, विश्वस्तरीय विनिर्माण के लिए। हमें मिलकर काम करना होगा अत्याधुनिक नवाचार के लिए। हमें मिलकर काम करना होगा नए युग की प्रौद्योगिकी के लिए।
- **बेवजह कानूनों की जकड़ से मुक्ति–** अनेक सेक्टरों में बहुत सारे रेगुलेशंस को हमने समाप्त कर दिया है। बेवजह कानूनों की जकड़ से मुक्ति ईज ऑफ़ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के उद्योग और व्यापार आज इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं।
- **राष्ट्रीय संकल्प–** देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदेभारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी। आज जिस गति से देश में नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर-दराज के इलाकों को जोड़ रही है, वो भी अभूतपूर्व है।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति- नेशनल मास्टर प्लान

- भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गतिशक्ति- नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है।
- **मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट–** विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, दोनों को बढ़ाना होगा। आपने देखा है, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है।
- **रक्षा उत्पादन–** भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी बना रहा है।
- आपका हर एक प्रॉडक्ट भारत का ब्रैंड एंबेसेडर है। देश के सभी मैन्यूफैक्चर्स को भी ये समझना होगा। आप जो प्रॉडक्ट बाहर भेजते हैं वो आपकी कंपनी में बनाया हुआ सिर्फ एक प्रॉडक्ट नहीं होता। उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, प्रतिष्ठा जुड़ी होती है।
- **स्टार्ट-अप्स–** हमने देखा है, कोरोना काल में ही हजारों नए स्टार्ट-अप्स बने हैं, सफलता से काम कर रहे हैं। कल के स्टार्ट-अप्स, आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है।

> छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी

- सुधारों को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है।
- **नियमों-प्रक्रियाओं की समीक्षा–** मैं आज आह्वान कर रहा हूं, केंद्र हो या राज्य सभी के विभागों से, सभी सरकारी कार्यालयों से। अपने यहां नियमों-प्रक्रियाओं की समीक्षा का अभियान चलाइए। हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर, खड़ी हुई है, उसे हमें दूर करना ही होगा।
- **नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति'–** आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' भी है। जब गरीब के बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गरीबी के खिलाफ लड़ाई का मैं साधन मानता हूं।
- **गरीबी के खिलाफ लड़ाई और मातृभाषा–** नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गरीबी के खिलाफ लड़ाई का साधन भाषा है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बहुत बड़ा शस्त्र बनने जा रहा है। गरीबी से जंग जीतने का आधार भी मातृभाषा की शिक्षा है, मातृभाषा की प्रतिष्ठा है, मातृभाषा का माहात्म्य है।
- **शिक्षा नीति और खेल–** नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक और विशेष बात है। इसमें स्पोर्ट्स को पाठ्येतर की जगह मेनस्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी प्रभावी माध्यम हैं, उनमें एक स्पोर्ट्स भी है।

- **भारत की बेटियां–** ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हों या ओलंपिक का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर हैं।
- **बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल–** आज मैं एक खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। दो-ढाई साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का प्रयोग किया गया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता

- भारत की प्रगति के लिए, 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए भारत का ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को ये संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएंगे।
- **ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र–** भारत आज जो भी कार्य कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो भारत को क्वांटम जंप देने वाला है– वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। मैं आज तिरंगे की साक्षी में 'नेशनल हाइड्रोजन मिशन' की घोषणा कर रहा हूं।
- **लंबित समस्याओं का समाधान–** 21वीं सदी का आज का भारत, बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है, जिनके सुलझने का दशकों से, सदियों से इंतजार था।
- धारा 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था- जीएसटी हो, हमारे फौजी साथियों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' हो, या फिर राम जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है।
- त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, या फिर जम्मू-कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार हुए बीडीसी और डीडीसी चुनाव, भारत अपनी संकल्पशक्ति लगातार सिद्ध कर रहा है।
- आज कोरोना के इस दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एअर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नये भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। भारत बदल रहा है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रूकता नहीं है।
- **आतंकवाद और विस्तारवाद की चुनौतियां–** आज दुनिया, भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है और इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़े हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है।
- आज देश के महान विचारक श्री अरबिंदो की जन्मजयंती भी है। साल 2022 में उनकी 150वीं जन्मजयंती है, वो कहते थे कि हमें उतना सामर्थ्यवान बनना होगा, जितना हम पहले कभी नहीं थे। हमें अपनी आदतें बदली होंगी, एक नए हृदय के साथ अपने को फिर से जागृत करना होगा।
- जिन संकल्पों का बीड़ा आज देश ने उठाया है, उन्हें पूरा करने के लिए देश के हर जन को उनसे जुड़ना होगा, हर देशवासी को इसे अपनाना (Own करना) होगा। देश ने जल संरक्षण का अभियान शुरू किया है, तो हमारा कर्तव्य है पानी बचाने को अपनी आदत से जोड़ना।
- मैं भविष्यद्रष्टा नहीं हूं, मैं कर्म के फल पर विश्वास रखता हूं। मेरा विश्वास देश के युवाओं पर है। मेरा विश्वास देश की बहनों-बेटियों, देश के किसानों, देश के प्रोफेशनल्स पर है। ये 'कैन डू जनरेशन' है, ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है।
- **विजन 2047–** मुझे विश्वास है कि जब 2047, आजादी का स्वर्णिम उत्सव, उस समय जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वे अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे वो सिद्धियां वही होंगीं जो आज देश संकल्प कर रहा है...ये मेरा विश्वास है।
- **राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम–** 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी एकजुटता है। हमारी प्राणशक्ति- राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना है। ■

14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा: नरेन्द्र मोदी

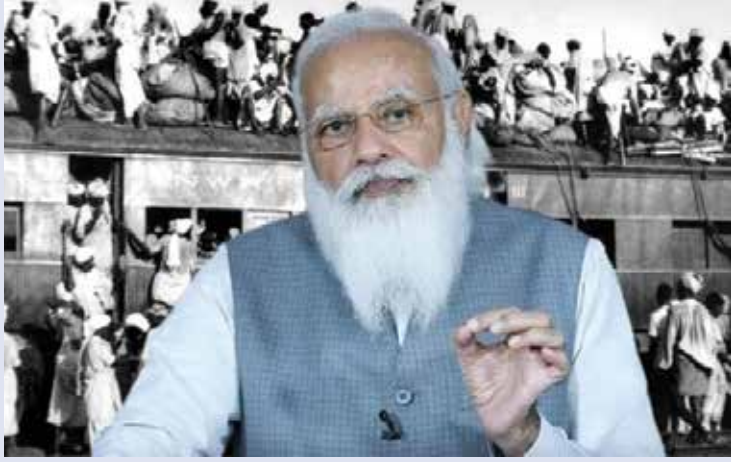

गत 14 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देशवासियों के संघर्षों और उनकी कुर्बानियों को याद करते हुये 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जायेगा।

अपने कई ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि विभाजन के दंश से प्रभावित लोगों के संघर्ष व बलिदान की स्मृति में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए हृदय से धन्यवाद है।

उन्होंने कहा कि विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों ने तुष्टिकरण की राजनीति और नकारात्मक शक्तियों को हावी होने का मौक़ा दिया। हमें इतिहास से सीख लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह गलती कभी दोहरायी न जाए। क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखते हैं, उन्हें बार-बार कष्ट सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने के फ़ैसले का अभिनंदन किया। अपने ट्वीट्स में श्री शाह ने कहा कि देश के विभाजन के समय हिंसा व घृणा के साये में विस्थापित हुए हमारे असंख्य बहनों व भाइयों के त्याग, संघर्ष व बलिदान की याद में मोदीजी ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संवेदनशील निर्णय पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि देश के विभाजन का घाव व अपनों को खोने के दुःख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' समाज से भेदभाव व द्वेष की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम व एकता को बल देगा। ■

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई, एसआईटी को सौंपी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझावों को स्वीकार करते हुए अपराध और हत्या जैसे जघन्य अपराधों की जांच 19 अगस्त को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी और कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार हुए लोगों की शिकायत दर्ज नहीं होने के आरोप 'निश्चित और सिद्ध' हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कई जनहित याचिकाओं पर एकमत से निर्णय दिया। इन याचिकाओं में चुनाव बाद हुई हिंसा की घटनाओं पर स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने अन्य सभी मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का भी आदेश दिया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराना आवश्यक है और इसके लिए सीबीआई ही ऐसी एजेंसी हो सकती है। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार कथित हत्याओं के कुछ मामलों में

भी प्राथमिकी दर्ज कराने में विफल रही। पीठ ने कहा, "इससे पता चलता है कि जांच को एक विशेष दिशा में ले जाने की मानसिकता थी।" अदालत ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने से सभी संबंधित लोगों में विश्वास जगेगा।"

अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा शुरुआत में बहुत से मामले दर्ज नहीं करने और अदालत के दखल या समिति के गठन के बाद ही कुछ मामले दर्ज करने के आरोप सही पाए गए हैं। ■

प्रधानमंत्री ने 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए विश्व नेताओं का आभार प्रकट किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार प्रकट किया।

भूटान के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आपका धन्यवाद, ल्योंचेन @PMBhutan। सभी भारतीय मैत्री के उन अनूठे और विश्वस्त संबंधों को महत्व देते हैं जिन्हें हम भूटान के साथ साझा करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद, मेरे दोस्त स्कॉट मॉरिसन। भारत भी ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा मूल्यों और जनता के प्रगाढ़ संबंधों पर आधारित अपनी सुदृढ़ जीवंत साझेदारी का सम्मान करता है।

प्रधानमंत्री श्री महिंदा राजपक्षे के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। भारत और श्रीलंका सहस्र वर्ष पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं, जो हमारी विशेष मैत्री की बुनियाद हैं।

प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा को उनकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत और नेपाल के लोग हमारे साझा सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों की बदौलत एकजुट हैं।

मालदीव के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मालदीव हमारा महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भयरहित, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में हमारा भागीदार है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोतबाया राजपक्षे के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं तथा भारत-श्रीलंका सहयोग को सभी क्षेत्रों में और ज्यादा मज़बूत बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि धन्यवाद, प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। भारत और मॉरीशस की जनता के बीच सदियों पुराने संबंधों के कारण हम दोनों देश समान मूलभूत मूल्यों और परंपराओं को साझा करते हैं। यही हमारी बेहद विशेष मैत्री की बुनियाद है।

इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री नफ्ताली बेनेट के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद महामहिम प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। मैं हमारी सरकारों और जनता के बीच संबंधों को मज़बूत बनाने तथा भारत-इज़रायल रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं। ■

स्थानीय भाषाओं और राजभाषा ने देश को एक करने का काम किया है: अमित शाह

गत 10 अगस्त को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे यहां लोकतंत्र के संस्कार नये नहीं हैं, दुनिया में सबसे पहला लोकतंत्र हमारे यहां ही था और इस संस्कार और संस्कृति को भाषा के बिना हम संजोकर नहीं रख सकते। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने भाषाओं को जो महत्व दिया और अंग्रेजी का यहां आधिपत्य न पड़ जाय उसकी सजगता दिखाई, इसी कारण आज हमारी भाषाएं समृद्ध हैं। स्थानीय भाषाएं भी समृद्ध हैं और दिन-प्रतिदिन राजभाषा हिन्दी भी समृद्ध हुई है।

गृह मंत्री ने कहा कि बहुत सारे देशों की न लिपि बची है और न ही भाषा बची है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि आज़ादी के बाद जितनी बोलियां थीं उनको भी हमने संरक्षित और संवर्धित रखा है और जितनी भाषाएं थीं उनको भी बचा कर रखा है। साथ ही जितनी लिपियां थीं वे भी देवनागरी के तत्वाधान में आगे बढ़ रही हैं। इससे देश की एकता और अखंडता में कोई दरार नहीं पड़ी, बल्कि स्थानीय भाषाओं और राजभाषा ने देश को एक करने का काम किया है। इस वजह से ही मेरे विचार से राजभाषा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है।

श्री शाह ने समिति के सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमे राजभाषा हिन्दी का विकास सहज रूप से स्थानीय भाषाओं की सखी के रूप में होना चाहिए। ■

समुद्री विवादों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत नौ अगस्त को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की। इस दौरान, प्रधानमंत्री ने समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत समावेशी समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिए पांच सिद्धांत प्रस्तुत किये और महासागरों के सतत उपयोग के वास्ते भारत के दृष्टिकोण 'सागर' का उल्लेख किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये 'समुद्री सुरक्षा को बढ़ावाः अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता' पर खुली परिचर्चा की अध्यक्षता के दौरान आतंकवाद और समुद्री अपराध के लिए समुद्री मार्ग का दुरुपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए चिंता जतायी।

उन्होंने कहा कि हमारी साझा समुद्री विरासत के संरक्षण एवं उपयोग के मद्देनजर पारस्परिक सहयोग के लिए हमे एक ढांचा बनाने की आवश्यकता है। ऐसा ढांचा कोई एक देश अकेले नहीं बना सकता। इसके लिए हम सभी के द्वारा संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

साथ ही उन्होंने जोर दिया कि महासागर दुनिया की साझा विरासत हैं और समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवनरेखा हैं। समुद्र विरासत साझा करने वाले देशों के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने पांच सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक प्रारूप तैयार किया जा सकता है। उन्होंने पहले सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए। वैश्विक समृद्धि समुद्री व्यापार के सहज संचालन पर निर्भर करती है। समुद्री व्यापार के समक्ष कोई भी बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो सकती है।

> संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले श्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं

मुक्त समुद्री व्यापार को सदैव ही भारत के सभ्यतागत लोकाचार का हिस्सा करार देते हुए श्री मोदी ने कहा कि नयी दिल्ली ने अपने दृष्टिकोण 'सागर'– क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं प्रगति– को आगे बढ़ाया है और यह क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के समावेशी बुनियादी ढांचे के निर्माण का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र बनाना है। मुक्त समुद्री व्यापार के लिए यह भी जरूरी है कि हम अन्य देशों के नाविकों के अधिकारों का भी पूरी तरह सम्मान करें।

दूसरे सिद्धांत को लेकर श्री मोदी ने कहा कि समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पारस्परिक विश्वास एवं भरोसे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह केवल इकलौता रास्ता है जिसके जरिए हम वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत पूरी परिपक्वता के साथ अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा के मुद्दों को हल करता है। तीसरे प्रमुख सिद्धांत के बारे में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों का एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण और समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना, प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए चौथे और पांचवें सिद्धांत रहे। श्री मोदी ने कहा कि हमारे महासागर जलवायु पर सीधा प्रभाव डालते हैं, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने समुद्री पर्यावरण को प्लास्टिक और तेल रिसाव के जरिये होने वाले प्रदूषण से बचाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए इन पांच सिद्धातों पर आधारित वैश्विक रोडमैप विकसित कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले श्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। परिचर्चा में यूएनएससी के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

परिचर्चा समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर केंद्रित थी। यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर पूर्व में चर्चा कर कई प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि, यह पहली बार था जब उच्चस्तरीय खुली बहस में एक विशेष एजेंडा के रूप में समुद्री सुरक्षा पर समग्र रूप से चर्चा की गई। ■

कांग्रेस सरकार में हर रक्षा सौदे में घोटाले हुए: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड के दो दिवसीय प्रवास पर 20 अगस्त, 2021 को देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंचने के बाद श्री नड्डा ने भानियावाला, चिद्दारवाला, नेपाली फार्म और रायवाला क्षेत्रों का दौरा किया। फिर श्री नड्डा हरिद्वार पहुंचे जहां कई संगठनात्मक बैठकें की गईं।

प्रवास के दौरान श्री नड्डा के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम भी थे। बैठक में राज्य के सभी पांच सांसद भी मौजूद रहे। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने किया।

इस प्रवास के दौरान श्री नड्डा ने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न नेताओं से भी बातचीत की और उनसे फीडबैक लिया।

श्री नड्डा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, राज्य पदाधिकारियों, कोर कमेटी और विभिन्न मोर्चा के साथ जमीनी स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को समझने के लिए चर्चा की।

अपने प्रवास के दूसरे दिन श्री नड्डा ने रेलवाला में 'सैनिक सम्मान' कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। फिर, उन्होंने भाजपा के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, महापौरों और ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की। इसके बाद श्री नड्डा ने साधुओं और धर्मगुरुओं से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।

विधायकों और मंत्रियों के साथ इन बैठकों के दौरान श्री नड्डा ने विधानसभा चुनावों के लिए स्थानीय मुद्दों के महत्व और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विधायकों से पार्टी संगठन के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि जिन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करें।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और पार्टी के विभिन्न संगठनों के प्रमुखों के साथ अलग से बैठक की। उन्होंने जिलाध्यक्षों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र के हर बूथ पर रहें और बूथ समितियों के सदस्यों से बातचीत करें। उन्होंने जिले के हर हिस्से का लगातार दौरा करने और मतदाताओं से संवाद सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री नड्डा ने राज्य सरकार और केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने 20 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की।

पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 21 अगस्त, 2021 को रायवाला (उत्तराखंड) में आयोजित पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में भाग लिया और पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में प्रदेश के कोने-कोने से पूर्व सैनिक शामिल हुए। श्री नड्डा के साथ पूर्व सैनिकों के इस सम्मान कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, प्रदेश प्रभारी एवं सांसद श्री दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी, राज्य सरकार में मंत्री एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण का काम देखने वाले श्री गणेश जोशी के साथ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं अधिकारी (रिटायर्ड) उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद से देश के आर्म्ड फोर्सेज में एक विशेष विश्वास जगा है। आज देश के जवानों को यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्रीजी की हर दीपावली किसी न किसी बॉर्डर पर जवान के साथ बीतती है, यह कोई छोटा संदेश नहीं है।

श्री नड्डा ने कहा कि नेतृत्व के बदलने से क्या फर्क पड़ता है, यह समझने की जरूरत है। 2011-12 में देश का रक्षा बजट लगभग 1,47,000 करोड़ रुपये था जो कि 2020-21 में बढ़कर लगभग 4,78,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें से भी लगभग 1,35,000 करोड़ रुपये नए अस्त्र-शस्त्र के लिए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है।

श्री नड्डा ने कहा कि सीमा पर बीआरओ द्वारा लगभग 3300 किमी की 61 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भारत-चीन सीमा पर 3812 किमी की 73 अन्य सड़कों का निर्माण कार्य तेज गति से

जारी है। साथ ही 100 किमी की 17 रोड टनल का निर्माण कार्य भी जोरों पर है।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासन में हर रक्षा सौदे में घोटाले हुए। हर खरीदारी में घोटाला किया गया। देश की सुरक्षा के लिहाज से किसी भी डिफेन्स डील में कोई फैसला न करना और भ्रष्टाचार करना, यही कांग्रेस सरकार की नीति बन गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद सेना के आधुनिकीकरण का काम तेज हुआ। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल का बेड़ा शामिल हो रहा है। साथ ही अपाचे, चिनूक, सर्फेस टू एयर मिसाइल और होवित्जर तोपें भी शामिल हो रही हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि पहली बार चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ का पद सृजित किया गया, बेहतर को-ऑर्डिनेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ मिलिट्री अफेयर्स का भी गठन किया गया। वन रैंक, वन पेंशन की मांग 1972 से चली आ रही थी लेकिन इसे भी पूरा किया आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने। उत्तराखंड में वन रैंक, वन पेंशन योजना से लगभग एक लाख पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं। अब तक इस योजना के तहत 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है जिससे सेना के लाखों जवान लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां सेना के सम्मान में शहीद धाम बनाने का निर्णय लिया है। मैं उन्हें इस पुण्य कार्य के लिए बधाई देता हूं।

श्री नड्डा ने 19 अगस्त को राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पौड़ी गढ़वाल के जवान दिवंगत सूबेदार राम सिंह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जायेगी।

साधु-संतों का सम्मान

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 21 अगस्त, 2021 को हरिद्वार (उत्तराखंड) में साधु-संतों का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले उन्होंने प्रदेश के जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और हरिद्वार में वार्ड-तीन, दुर्गा नगर के बूथ 12 के अध्यक्ष श्री पमोद पाल के घर भी पहुंचे। उन्होंने ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च्छ में बाबासाहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक के साथ-साथ प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री अनिल बलूनी भी उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्रीरामचरितमानस में लिखा है– मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू।। अर्थात् संतों का समागम सर्वथा आनंदमय और कल्याणमय है, जो जगत् में चलता-फिरता तीर्थराज (प्रयाग) है। पवित्र श्रावण मास में उन्हें पूज्य संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए वे अपने-आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी पूज्य संतों के चरणों की वंदना करते हुए उनके स्नेहिल आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सनातन धर्म की सेवा में समर्पित रहते हुए देश के विकास के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हम सबका सपना था लेकिन किसी भी सरकार के पास इसके लिए इच्छाशक्ति नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी देशवासियों का यह सपना भी पूरा हुआ। प्रधानमंत्रीजी के कर-कमलों से शिलान्यास होने के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का श्री केदारनाथजी और श्री बदरीनाथजी के प्रति कितनी गहरी आस्था और श्रद्धा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां के विकास की वे स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और जो भी जरूरी होता है, उसे वे पहले ही पूरा कर देते हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं आज सभी पूज्य संतों से आशीर्वाद मांगता हूं कि आप मुझे संगठन को और मजबूती देने और मानवता की सेवा के हमारे संकल्प को ताकत दें। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि कोई ऐसा प्रदेश न हो जहां कमल न खिले और हर प्रदेश में हमें जनता की सेवा का अवसर मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति से देश की राजनीति में बहुत बदलाव हुए हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे और भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ■

संगठनात्मक नियुक्तियां

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 अगस्त 2021 को श्री नागेन्द्र जी को बिहार एवं झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया। उनका केंद्र रांची रहेगा। वहीं, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री भीखुभाई दलसानिया को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया। ■

ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 नए केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 अगस्त 2021 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 नए केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी समाज से 27 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल होना तथा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा ओबीसी समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, मोर्चा प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद श्री अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के लक्ष्मण, ओबीसी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री एस.पी. सिंह बघेल, ओबीसी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दारा सिंह चौहान, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष व सांसद श्री नायाब सिंह सैनी, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री श्री हंसराज अहीर, सांसद व ओबीसी मोर्चा महामंत्री श्री संगम लाल गुप्ता तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री यशपाल स्वर्णा और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता भी उपस्थित रहे।

> आज भारत के मंत्रिमंडल में 35 प्रतिशत मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। नए मंत्रिमंडल में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है

श्री नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में 27 ओबीसी मंत्री बने हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। जिसको राजनीतिक कार्य के बारे में रुचि हो, उसे ही समझ आता है कि किसी व्यक्ति के आने से या किसी व्यक्ति के जाने से क्या फर्क पड़ता है। आज भारत के मंत्रिमंडल में 35 प्रतिशत मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। नए मंत्रिमंडल में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए संगठन के साथ घंटों चर्चा की, तब ये भारत का गुलदस्ता तैयार हुआ है।

उन्होंने कहा कि नए मंत्रिमंडल में 12 एससी समुदाय से, 8 एसटी समुदाय से, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से और 11 महिलाएं शामिल हुए हैं। क्या पहले, कांग्रेस की सरकार में समाज का ऐसा प्रतिनिधित्व कभी हुआ था? इसकी वजह उनकी मानसिकता थी जो ये सोचते थे कि देश चलाना सिर्फ और सिर्फ एक परिवार से ही संभव है।

श्री नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों ने खुद को किसान नेता के रूप में उभारा, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसी ने खुद को दलित नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं किया। किसी ने खुद को युवा नेता बनने की कोशिश की, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की समस्या के निराकरण के लिए वाकई किसी नेता ने अपनी प्रतिबद्धता साबित की है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। कांग्रेस का चुनाव के वक्त एक झुनझुना होता था कि किसानों का कर्ज मुफ्त कर देंगे लेकिन इस पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन आज 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों के खाते में हस्तांतरित किये हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पहले किसने मना किया था ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया। जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया। राज्य सभा में यह बिल आने पर पहले इसे सेलेक्ट कमेटी भेजा गया। वहां से लौटने के बाद कांग्रेस ने फिर इसका विरोध किया था, लेकिन जब सदन में हम सामर्थ्यवान बने तो फिर इस बिल को संवैधानिक दर्जा मिला। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को 27 प्रतिशत का आरक्षण मिल सके इसमें कौन रुकावट ला रहा था? प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया है। पहले की सरकारों को इसका खयाल क्यों नहीं आया? नीट में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री मोदीजी ने की है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देने और स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर गांव की महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। ■

भाजयुमो की 'युवा संकल्प यात्रा' में युवाओं की भारी भागीदारी

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के महोत्सव के अंतर्गत आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा की 'युवा संकल्प यात्रा' में देश भर के युवाओं ने बढ़-चढ़कर सहभाग किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 75 स्थानों पर 75 किलोमीटर साइकिल रैली और मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का प्रारंभ 15 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर से हुआ। समापन समारोह 17 अगस्त, 2021 को लद्दाख में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या के साथ साथ लद्दाख भाजपा के अध्यक्ष और संसद सदस्य श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल उपस्थित थे।

लद्दाख इकाई के भाजयुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या ने कहा, "आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 'युवा संकल्प यात्रा' का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रवादी मूल्य और राष्ट्रीयता की भावना को बनाये रखना और प्रेरित करना है। यह यात्रा जब लद्दाख में समाप्त हो रही है तो हमने पूरे देश में 75 स्थानों पर 75 किलोमीटर की दूरी साइकिल रैली और मैराथन के माध्यम से तय की है।

उन्होंने कहा कि भाजयुमो ने लद्दाख को अंतिम गंतव्य के रूप में इसलिए चुना क्योंकि यह नए भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। आजादी के बाद से लद्दाख को अपनी संस्कृति, भाषा और कला की रक्षा के लिए केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की जाती रही थी। भारत के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी थी और न ही कोई प्रधानमंत्री था, जिसने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई हो। 2019 में ही हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प को दर्शाते हुए न केवल धारा 370 को हटाया, बल्कि लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा भी दिया। यह हम सबके लिए गौरवकारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख वास्तव में साहस और दृढ़ विश्वास की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करता है और नए भारत के निर्माण में लद्दाख की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवा संकल्प यात्रा का आयोजन न्यू इंडिया के संदेश और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 के लिए भारत के दृष्टिकोण और युवाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। साइकिल चलाने और दौड़ने के कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के सभी युवाओं को स्वस्थ और लचीला राष्ट्र बनाने के लिए फिट और मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। ■

महिला मोर्चा ने 75 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया

भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने 15 अगस्त, 2021 को देश में 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थान एवं स्मारकों पर कार्यक्रम आयोजित किए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'आजादी का महोत्सव' समारोह के तहत महिला मोर्चा ने स्वतंत्रता आंदोलन की 75 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।

महिला मोर्चा ने इन स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थानों की पहचान की है, जहां उनकी स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानथी श्रीनिवासन ने तमिलनाडु के कड्डालूर की महान वीरांगना अंजलई अम्मल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा अंजलई अम्मल का जन्म 1890 में हुआ था और उन्होंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। जब गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो अंजलई अम्मल उसमें कूद पड़ी। यह सार्वजनिक जीवन में उनका पहला कदम था। अंजलई अम्मल ने भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नरसंहार के लिए जिम्मेदार एक ब्रिटिश अधिकारी की प्रतिमा को हटाने के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसलिए अंजलई अम्मल को अपनी 9 वर्षीय बेटी अम्माकन्नू के साथ उस संघर्ष में भाग लेने के कारण जेल हुई।

उन्होंने आगे कहा कि अंजलई अम्मल 1932 में हुए स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वेल्लोर जेल भेजे जाने पर वह गर्भवती थीं। गर्भावस्था के बावजदू जेल की जिंदगी का उनको कोई डर नहीं था। उन्हें अपनी बच्चे की डिलीवरी के लिए अंग्रेजों से एक महीने की पैरोल लेनी पड़ी। लेकिन अपने बेटे के जन्म के 2 सप्ताह के भीतर, अंजलई अम्मल अपने नवजात बच्चे के साथ वापस जेल में आ गईं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनका दृढ़ संकल्प ऐसा था। नतीजतन, गांधीजी ने उन्हें दक्षिण की झांसी की रानी कहा। इसी तरह, अन्य जगहों पर महिला मोर्चा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। ■

उज्ज्वला योजना से बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के संकल्प को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है: नरेन्द्र मोदी

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में करोड़ों शौचालय बनवाए जा रहे हैं; गरीब परिवारों के लिए 2 करोड़ से भी अधिक घर, इनमें से ज्यादातर महिलाओं के नाम पर; ग्रामीण सड़कें; 3 करोड़ परिवारों को मिला बिजली कनेक्शन और आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक के चिकित्सा उपचार के लिए कवर दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत 10 अगस्त को महोबा, उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- पीएमयूवाई) का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत भी की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें रक्षाबंधन से पहले यूपी की बहनों को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से जिन लोगों का जीवन रोशन हुआ है, उनकी संख्या अभूतपूर्व है और इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की हैं। यह योजना, 2016 में यूपी के बलिया, स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता मंगल पांडे की भूमि से शुरू की गई थी।

श्री मोदी ने कहा कि आज उज्ज्वला का दूसरा संस्करण भी यूपी की वीरभूमि-महोबा से शुरू किया गया है। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती के एक और सपूत मेजर ध्यान चंद या दद्दा ध्यान चंद का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे उन लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं।

> वर्ष 2014 में कुल जितने गैस कनेक्शन थे उससे कहीं अधिक गैस कनेक्शन पिछले 7 वर्षों के दौरान दिए गए हैं

श्री मोदी ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल और स्कूल ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं है जिनकी पूर्ति के लिए देशवासियों को दशकों तक इंतजार करना पड़ा। ऐसी कई चीजों को दशकों पहले देशवासियों को सुलभ कराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएंगी, जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में सरकार ने ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया है।

उन्होंने ऐसी कई उपलब्धियां गिनाईं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में करोड़ों शौचालय बनवाए जा रहे हैं; गरीब परिवारों के लिए 2 करोड़ से भी अधिक घर, इनमें से ज्यादातर महिलाओं के नाम पर; ग्रामीण सड़कें; 3 करोड़ परिवारों को मिला बिजली कनेक्शन; आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक के चिकित्सा उपचार के लिए कवर दिया जा रहा है; मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण एवं पोषण के लिए प्रत्यक्ष धन अंतरण; कोरोना काल में महिलाओं के जन धन खातों में सरकार द्वारा 30 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए; जल जीवन मिशन के तहत हमारी बहनों को पाइप से जल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव आया है।

श्री मोदी ने कहा कि बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मुफ्त गैस कनेक्शन का कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस के बुनियादी ढांचे का कई गुना विस्तार सुनिश्चित हुआ है। पिछले 6-7 वर्षों के दौरान 11 हजार से भी अधिक एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में इन केंद्रों की संख्या वर्ष 2014 के 2 हजार से बढ़कर 4 हजार हो गई है।

श्री मोदी ने कहा कि हम शत-प्रतिशत गैस कवरेज के बहुत करीब हैं क्योंकि वर्ष 2014 में कुल जितने गैस कनेक्शन थे उससे कहीं अधिक गैस कनेक्शन पिछले 7 वर्षों के दौरान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड सहित पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से कई लोग काम के लिए गांव से शहर या दूसरे राज्यों में चले गए। वहां उन्हें निवास प्रमाण-पत्र की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला 2.0 योजना ऐसे ही लाखों परिवारों को सबसे अधिक राहत पहुंचाएगी। ■

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–पाम ऑयल के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान देते हुए केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना का सूत्रपात तथा वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपये निर्धारित, जिसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपये वहन करेगी

गत 18 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ताड़ के तेल (पाम ऑयल) के लिये एक नये मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी गई, जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल–पाम ऑयल मिशन (एनएमईओ-ओपी) है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है और इसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। खाद्य तेलों की निर्भरता बड़े पैमाने पर आयात पर टिकी है, इसलिये यह जरूरी है कि देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाई जाए। इसके लिये पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाना बहुत अहम है।

इस योजना के लिये 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपये का वहन करेगी। इसमें 2,196 करोड़ रुपये राज्यों को वहन करना है। इसमें आय से अधिक खर्च होने की स्थिति में उस घाटे की भरपाई करने की भी व्यवस्था शामिल की गई है।

इस योजना के तहत प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया जाये और इस तरह आखिरकार 10 लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूरा कर लिया जाये। आशा की जाती है कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) की पैदावार 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंच जायेगी। इस योजना से पाम ऑयल के किसानों को बहुत लाभ होगा, पूंजी निवेश में बढ़ोतरी होगी, रोजगार पैदा होंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी।

मोदी सरकार ने तिलहन और पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये हैं। वर्ष 2014-15 में 275 लाख टन तिहलन का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 365.65 लाख टन हो गया है। पाम ऑयल की पैदावार की क्षमता को मद्देनजर रखते हुये वर्ष 2020 में भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान (आईआईओपीआर) ने पाम ऑयल की खेती के लिये एक विश्लेषण किया था। उसने लगभग 28 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। लिहाजा, ताड़ के पौधे लगाने की अपार क्षमता मौजूद है, जिसके आधार पर कच्चे ताड़ के तेल की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है।

मौजूदा समय में ताड़ की खेती के तहत केवल 3.70 लाख हेक्टेयर का रकबा ही आता है। अन्य तिलहनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ताड़ के तेल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना अधिक होता है। इसके अलावा एक हेक्टेयर की फसल से लगभग चार टन तेल निकलता है। इस तरह, इसकी खेती में बहुत संभावनाएं हैं।

गौरतलब है कि आज भी लगभग 98 प्रतिशत कच्चा ताड़ का तेल आयात किया जाता है। इसे मद्देनजर रखते हुए योजना शुरू करने

का प्रस्ताव किया गया है, ताकि देश में ताड़ की खेती का रकबा और पैदावार बढ़ाई जाये। प्रस्तावित योजना में मौजूदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तेल ताड़ कार्यक्रम को शामिल कर दिया जायेगा।

भारत ने 100 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त किया

भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, 100 गीगावॉट के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार गई। भारत 12 अगस्त, 2021 को स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में पांचवें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने अपने लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रतिबद्ध है।

जबकि 100 गीगावॉट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है, 50 गीगावॉट क्षमता स्थापित करने का काम जारी है और 27 गीगावॉट के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ा दिया है। यदि बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाए तो स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 146 गीगावॉट बढ़ जाती है।

100 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता की उपलब्धि, 2030 तक 450 गीगावॉट के अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ■

मानसून सत्र के दौरान संसद ने पारित किए 22 विधेयक

मानसून सत्र-2021 के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 22 विधेयक पारित किए गए, जिनमें 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों से संबंधित दो विनियोग विधेयक और 2017-2018 के लिए अधिक अनुदान की मांग शामिल हैं, जिन्हें लोकसभा द्वारा पारित किया गया और राज्यसभा को भेजा गया। इन विधेयकों को अनुच्छेद 109(5) के तहत पारित माना जाता है।

गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई, 2021 को शुरू हुआ। इसे 11 अगस्त, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थागित कर दिया गया। इस सत्र में 24 दिनों की अवधि में 17 बैठकें आयोजित की गईं।

अध्यादेशों का स्थान लेने वाले चार विधेयक अर्थात न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतिकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021; दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021 तथा आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मॉनसून सत्र से पहले घोषित किया गया था, पर विचार किया गया और सदनों द्वारा पारित किया गया। संसद के सदनों द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं:

आर्थिक क्षेत्र/कारोबार को सुगम बनाने के उपाय

- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 में प्रावधान है कि यदि लेनदेन 28 मई, 2012 से पहले किया गया था, तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी।
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं को उनके अपने धन तक आसान और समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है। इस विधेयक में यह प्रदान करने का प्रस्ताव है कि किसी बैंक पर लागू किए गए मोरिटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं।

परिवहन क्षेत्र में सुधार

- नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक, 2021 में भारत में नौवहन के लिए सहायता के विकास, रखरखाव और प्रबंधन संबंधी प्रावधान हैं। अन्य प्रावधान हैं– नौवहन के लिए समुद्री सहायता के संचालकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन, समुद्री सहायता के ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास; समुद्री संधियों और अंतरराष्ट्रीय उपकरणों, जिसमें भारत एक पक्ष है, के तहत दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करना आदि।
- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 अंतर्देशीय जल के माध्यम से किफायती और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देता है, देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग और परिवहन से संबंधित कानून के आवेदन में एकरूपता लाता है, पोत परिवहन के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जीवन और कार्गो की सुरक्षा तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रावधान पेश करता है आदि।

शैक्षिक सुधार

- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन में निर्देश और अनुसंधान प्रदान करता है।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश, लद्दाख में 'सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करना चाहता है।

सामाजिक न्याय क्षेत्र में सुधार

- संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि राज्य सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची/केंद्रशासित प्रदेश सूची तैयार करने और इसे बनाए रखने का अधिकार है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 यह प्रावधान करता है कि अदालत की बजाय, जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) गोद लेने के आदेश जारी करेंगे। विधेयक में कहा गया है कि गंभीर अपराधों में वे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए अधिकतम सजा सात वर्ष से अधिक कारावास की है और न्यूनतम सजा या तो निर्धारित नहीं है या सात वर्ष से कम है। ■

समाज और विचारधारा

दीनदयाल उपाध्याय

गतांक का शेष...

समाज के साथ उस नाते से हमारे आत्मीयता के संबंध हैं। समाज का विचार करनेवालों ने समानता का संबंध रखा। उन्होंने कहा कि सब आदमी बराबर हैं। लेकिन इसका उत्तर देनेवालों ने कहा कि जिंदगी में कहीं बराबरी नहीं, कुछ में ज्यादा शक्ति होती है, कुछ में कम। कुछ मामलों में हम भिन्न हैं। प्रकृति ने सबके अंदर भेद रखा है। सबके गुण और शक्ति अलग-अलग हैं। तो समाज का ही विचार करनेवालों ने पुनः इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि यह भेद समाज व्यवस्था के कारण है। समाज व्यवस्था के कारण जिसको पढ़ने को मिलता है, उसका विकास हो जाता है। कुछ अपनढ़ रह जाते हैं तो उनका विकास नहीं होता। परंतु यह तर्क भी बहुत दूर तक नहीं चल सकता। यदि ऐसा ही हो तो संपन्न लोगों के यहां तो कोई मंदबुद्धि या मूर्ख न रहे। कुछ ने कहा कि पूर्व जन्म के कारण भेद होते हैं तो समाज का विचार करनेवालों ने कहा कि यह पूर्वजन्म का विचार तो ग़रीबों को संतोष कराने के लिए है। किसी कारण से हो, तो भी यह सत्य है कि भेद मौजूद हैं। शक्ति में भेद है। गुण-कर्म में भेद है। मानव के आगे भी विचार करना चाहिए। प्रत्येक जीवमान का एक ही स्तर पर विचार करना चाहिए और कुछ लोग उसका विचार कर भी रहे हैं।

यह सत्य है कि समानता सत्य को प्रगट नहीं करती। आत्मीयता ही आधार हो सकता है। आत्मीयता इसलिए क्योंकि सबकी आत्मा एक है। जैसे क्या शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में समानता है? क्या सब अंग बराबर हैं? नहीं! फिर कौन सी ऐसी चीज़ है, जिसकी रक्षा करना नितांत आवश्यक है। किसी ने कहा कि हाथ या गले में से एक कटवाना पड़ेगा तो हाथ तो बचेगा, ऐसा सोचकर कोई गला कटवाने के लिए तैयार नहीं होगा। हाथ का दुःख भी मालूम होता है। क्योंकि संपूर्ण शरीर में आत्मीयता का भाव है। समानता का विचार ग़लत है।

समानता कैसी, इसका विचार भी मार्क्स ने किया है। क्या सबको चार रोटी देंगे, इससे समानता हो जाएगी? दो रोटी खानेवाले को चार रोटी खिलाई जाएं तो अन्याय ही होगा। जैसे कोई दिल्ली के सज्जन एक पठान के साथ मित्रता के कारण उसके देश में गए, बहुत लोगों ने स्वागत किया। लालाजी भोजन के लिए तैयार बैठे थे कि रोटियां रख दी गईं। लाला जी ने 'इतनी रोटी नहीं खाई जाएंगी' कहकर आनाकानी की। परंतु उनका आग्रह मानकर खाना प्रारंभ तो कर दिया परंतु आधी रोटियां मुश्किल से खाईं और शेष के लिए असमर्थता बताने पर वह पठान बंदूक ले आया और बोला, 'खाता है कि नहीं, वहां जाकर बदनामी करेगा कि मुझे भूखा रख दिया।' इस प्रकार दो खानेवाले को चार खिलाना अन्याय हुआ और जो ग़रीब छह खानेवाला है, यदि उसे चार दीं तो वह भूखा रह जाएगा। समानता ऐसे नहीं होती। ऐसी समानता तो जेल में होती है और कपड़ा यदि एक समान दिया तो बड़े शरीर वाले को तो पाजामे का कच्छा ही रह जाएगा और छोटे शरीर वाले की कमीज़ भी बन जाएगी। प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार लेना और उसकी आवश्यकतानुसार उसे देना। यदि यह नहीं हुआ और सबको पांच घंटे काम करना चाहिए, ऐसा नियम बनाया तो कमजोर की तो मुसीबत हो जाएगी। तृतीय वर्ष में शारीरिक करने के पश्चात् कुछ को तो लौटकर आना ही बोझ मालूम देता था और कुछ तो उसके पहले और बाद में भी दंड-बैठक लगाते थे। 'हाथी को मन भर और चींटी को कण भर' इसीलिए कहा है। यदि दोनों का औसत लगा लिया तो हाथी का बीस सेर से क्या होगा और चींटी तो बीस सेर कभी समाप्त नहीं कर पाएगी। समानता वाले औसत के नियम से ही विषमता बढ़ाते हैं।

प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह सिद्धांत तो बड़ा अच्छा है, पर इसका निर्धारण कैसे हो? योग्यता और आवश्यकता को कौन तय करेगा? उन्होंने कहा, 'राज्य तय करेगा।' राज्य माने सरकारी अधिकारी। वे भी तो मानव हैं। वे पहले अपनी आवश्यकता देखेंगे, फिर अपने आत्मीय जनों की मान लो, चीनी का परमिट तहसीलदार को बनाना है और उसके मित्र के यहां शादी है तो दूसरे नामों से भी वह उसके लिए परमिट काट लेगा। शेष लोगों की आवश्यकता उसे उस प्रकार की नहीं दिखाई देती। सरकार को प्रमुख बना दिया जाए तो प्रत्येक काम में यही बनता है। योग्यता में हम तो चार घंटे भी काम करें तो बहुत हो गया। दूसरों के लिए 'आराम हराम है' का नारा अपने लिए तो इतना काम करते हैं, क्या चार घड़ी आराम नहीं करेंगे, यह तर्क रहता है।

इस सबका अर्थ यही है कि इस समानता के विचार को बदला जाए। इसको बदलकर आत्मीयता को आधार बनाया जाए। मूलतः ग़लती यहीं पर खड़ी है कि हमने व्यक्ति के सुख-दुःख को प्रमुख रखा और दूसरों के प्रति घृणा फैलाकर कि 'यह तुम्हारे पसीने की कमाई से पल रहा है। इस तरह संघर्ष को आधार बनाकर यह नारा लगाया

कि हम मजदूरों का संगठन करते हैं। मजदूर को बताया जाता है कि तुम तो आठ घंटे काम करते हो और यह मैनेजर तो केवल कुरसी पर बैठकर चला जाता है। उसे घर जाकर भी चिंता के कारण नींद नहीं आती इसकी उसे कल्पना नहीं दी जाती। उसे यही कहा जाता है कि तू आठ घंटे काम करता है, काम कम करो और दूसरी ओर मजदूरी अधिक लो, ऐसी मांग करके संघर्ष करो। इस प्रकार आवश्यकता तो बढ़ती जाएगी और योग्यता कम होती जाएगी, और सारे देश में यही स्थिति रही तो एक दिन किसी को रोटी नहीं मिलेगी।

समाजवादी ढांचे में अभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। दो व्यवस्थाएं प्रारंभ होंगी। आवश्यकता की दृष्टि से राशनिंग और काम की दृष्टि से जबरदस्ती दबाव। आज कम्युनिस्ट दूसरों को कहता है– हड़ताल करो, लेकिन उसके राज्य में हड़ताल नहीं।

उसके विपरीत हमारा विचार है कि समाज की स्वतंत्र सत्ता है और व्यक्ति की भी स्वतंत्र, समाज की सेवा ही व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है। समाज के लिए व्यक्ति के कर्म उसके लिए भगवान को प्राप्त करने की साधना है। उससे ही वह समाज की सेवा करता है। परिवार में मां की आवश्यकता क्या है, वह घर में सबको खिलाने के बाद कुछ बच गया तो खाएगी और योग्यता देखिए कि सुबह से शाम तक काम करती है, सबसे पहले जागती है और सबसे अंत में सोती है। कभी अस्वस्थ है तो भी बच्चे को भूखा नहीं जाने देगी। ममता ही उससे काम कराती है। देने की योग्यता अधिक-से अधिक और लेने की कम-से-कम यह रहा तो फिर कभी कमी नहीं रहेगी। जितना दें, देते चले जाएं। कभी मन में असंतोष नहीं होगा। यहां काम करने में भाव का केंद्र समाज बन जाता है। समाज का भाव होता है तो आत्मीयता के कारण।

हमारा विचार है कि समाज की स्वतंत्र सत्ता है और व्यक्ति की भी स्वतंत्र, समाज की सेवा ही व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है। समाज के लिए व्यक्ति के कर्म उसके लिए भगवान को प्राप्त करने की साधना है

पूंजीवादी व्यवस्था में भी 'मार्केटिंग इकोनॉमी' की बात सोची जाती है। उसमें कर्म का केंद्र स्वार्थ ही रहता है। परंतु यहां तो कुम्हार मटका बनाता था और सोचता था कि यह मटका खरीदने के लिए भगवान आएंगे। इसलिए उसे काम करते हुए भी आनंद आता था और वह प्रयत्न करता था कि वह अच्छे से अच्छा मटका बनाए और अधिक से अधिक बनाए। यही भक्ति है। रात में जागकर भी काम करना पड़ेगा तो करेगा। संघ शिक्षा वर्ग में व्यवस्था करनी है तो जिस प्रकार कार्यकर्ता को आनंद होता है, उससे उसका विकास होता है। कार्य करने का खुलकर मौक़ा मिलता है। लेकिन दूसरी व्यवस्था में तो जबरदस्ती का भाव रहता है। सारे सूत्र कुछ लोगों के हाथ में रहते हैं। वस्तुतः 'यह काम मेरा है' इसलिए मेरा कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक कार्य करें। जिस प्रकार हाथ जितना काम करे, शरीर के लिए उसे आनंद ही होता है। हाथ को डांटा भी नहीं जाता। यह सब आत्मीयता के भाव के कारण है।

अनेक प्रकार की विचारधाराओं में जो ग़लती है कि वह व्यक्ति और समाज का संतुलन नहीं बना पाते, वहीं भारतीय दृष्टिकोण दोनों की चैतन्यमयी सत्ता को मानकर आत्मीयता का परस्पर संबंध स्थापित करता है और इस कारण समाज के लिए किए गए कार्य कर्तव्य हैं। वह इसे साधना मानकर चलता है, इसी भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का मैंने प्रयत्न किया है। ■

(समाप्त)

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, नई दिल्ली; जून २०, १९६३)

राज्यों को 49,355 करोड़ रुपये का अनुदान जारी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आय से अधिक खर्च होने पर होने वाले राजस्व घाटे (पीडीआरडी) की भरपाई करने के लिये नौ अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके। आयोग ने सिफारिश की थी कि 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिया जाए।

यह अनुदान प्राप्त करने के लिये कौन से राज्य पात्र हैं, इसका फैसला वित्त आयोग करता है। वह राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर फैसला करता है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिये मूल्यांकन किया गया।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपये (41.67 प्रतिशत) की रकम जारी की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिये जिन राज्यों की सिफारिश की थी, उनमें आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ■

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं रहे

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त को लखनऊ में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। श्री सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी दलों के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री सिंह के सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की।

कल्याण सिंहजी ने समाज के वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों को आवाज दी: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस दुःख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। कल्याण सिंह जी...राजनेता, वरिष्ठ प्रशासक, जमीनी नेता और बहुत अच्छे इंसान थे। वह अपने पीछे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। उनके बेटे श्री राजवीर सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक उत्थान में कल्याण सिंहजी के योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी आभारी रहेंगी। भारतीय मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी और वह हमारी सदियों पुरानी परंपराओं पर गर्व किया करते थे। श्री मोदी कहा कि कल्याण सिंहजी ने समाज के वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों को आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रयास किए।

बाद में 22 अगस्त को लखनऊ पहुंचकर श्री मोदी ने श्री कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंहजी के माता-पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि अपने माता-पिता द्वारा दिए गए नाम को सार्थक कर दिया। वो जीवन भर जन-कल्याण के लिए जिए, उन्होंने जन-कल्याण को ही अपना जीवन-मंत्र बनाया और भारतीय जनता

संक्षिप्त जीवन-परिचय

(5 जनवरी, 1932 - 21 अगस्त, 2021)

- श्री कल्याण सिंह का जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था।
- वे स्कूल के दिनों से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे।
- श्री सिंह पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ जिले के अतरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए।
- वे अतरौली विधानसभा क्षेत्र से दस बार विधायक चुने गए।
- उन्होंने 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 24 जून, 1991 - 6 दिसंबर, 1992 तक पहली बार और 21 सितंबर, 1997 - 12 नवंबर, 1999 तक दूसरी बार प्रदेश की सेवा की।
- वे 2004 में बुलंदशहर और 2009 में एटा से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए।
- वह 2014 में राजस्थान के 21वें राज्यपाल बने और 2019 तक सेवा की।
- श्री सिंह का 21 अगस्त, 2021 को स्वर्गवास हो गया।

पार्टी, भारतीय जनसंघ, पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया।

श्री मोदी कहा कि कल्याण सिंहजी भारत के कोने-कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय में वे जन-कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गर्वनर की जिम्मेदारी हो, हमेशा हरेक के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। जन-सामान्य के विश्वास का प्रतीक बने।

उन्होंने कहा कि देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनकी भरपाई के लिए, उनके आदर्शों और उनके संकल्पों को लेकर अधिकतम पुरुषार्थ करें और हम उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्रीराम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुःख की घड़ी में इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहां के मूल्यों, यहां के आदर्शों, यहां की संस्कृति, यहां की परम्पराओं में विश्वास करने वाले हर दुःखी जन को प्रभु राम ढांढस दें, यही प्रार्थना करता हूं।

कल्याण सिंहजी ने अपने कृतित्व और सेवा भाव से एक अमिट छाप छोड़ी : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय जन-प्रतिनिधि और जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी को मज़बूत बनाने एवं संगठन को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाने वाले श्री कल्याण सिंहजी के निधन से दुःखी एवं स्तब्ध हूं। वे सच्चे अर्थों में ऐसे जननेता थे जिन्होंने समाज के कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था।

श्री नड्डा ने कहा कि ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी श्री कल्याण सिंहजी ने अपने कृतित्व और सेवा भाव से देश के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका संपूर्ण जीवन जनता-जनार्दन की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने सिद्धांतों से कभी भी समझौता न करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मशाल सदैव जलाई रखी और पूरी जिंदगी शोषितों, वंचितों व पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ते रहे।

उन्होंने कहा कि किसान परिवार में जन्म लेने वाले श्री सिंह बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे शिक्षक भी रहे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों में जागरुकता पैदा की और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। उनके निधन से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। कल्याण सिंहजी का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सेवा के लिए तैयार करने वाले 'बाबू जी' की छवि सदैव हमारे मन-मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे।

उन्होंने कहा कि श्री कल्याण सिंह 1967 में पहली बार विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1967 से 1980 तक लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस बीच आपातकाल के समय वे लगभग 21 महीने जेल में भी रहे। आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 में उत्तर प्रदेश में बनी सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद वे उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री बने। वे 24 जून, 1991 से 6 दिसंबर, 1992 तक और 21 सितंबर, 1997 से 12 नवंबर, 1999 तक, दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई। अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने जो प्रतिष्ठा अर्जित की वो बहुत ऊंची थी। भारत के सांस्कृतिक उत्थान में श्री कल्याण सिंहजी के अमूल्य योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनका ऋणी रहेगी। भारत की महान विरासत और परंपराओं में उनकी अथाह श्रद्धा थी। श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय थी। वे किसानों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास करते रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धेय कल्याण सिंहजी के शोकाकुल परिवार एवं उनके सहयोगियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

वे भारतीय राजनीति के प्रमुख और एक जमीनी नेता थे: लालकृष्ण आडवाणी

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक

संदेश जारी किया। उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा कि मुझे अपने करीबी सहयोगी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंहजी के निधन से गहरा दुःख पहुंचा है। भारतीय राजनीति के प्रमुख और एक जमीनी नेता कल्याण सिंहजी उत्तर प्रदेश की पहली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक परिश्रम कर स्वयं को एक लोकप्रिय जननेता के तौर पर स्थापित किया और राज्य की समग्र प्रगति में अपना योगदान दिया।

कल्याण सिंह 'श्रीराम जन्मभूमि' आंदोलन के एक बड़े नेता थे: अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि श्री कल्याण सिंह का निधन उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने से हमारी पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देशभर, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गरीबों और पिछड़ों ने अपना एक हितचिंतक गंवाया है।

श्री शाह ने कहा कि श्री कल्याण सिंह 'श्रीराम जन्मभूमि' आंदोलन के एक बड़े नेता रहे और इस आंदोलन के लिए सत्ता त्यागने में उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जब 'श्रीराम जन्मभूमि' का शिलान्यास हुआ, उसी दिन उनकी बाबूजी से बात हुई थी और उन्होंने बड़े हर्ष और संतोष के साथ कहा था कि उनके जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया है। उनका पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास व ग़रीबों को समर्पित रहा और वे इस राज्य को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए सदैव कार्यरत रहे।

श्री शाह ने कहा कि कल्याण सिंह जी का एक बहुत ही ग़रीब तबक़े से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवनभर संघर्षरत रहना, समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये सब हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक रहेगा।

कल्याण सिंह ने देश और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कई ट्वीट कर कहा कि श्री कल्याण सिंह के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असम्भव है। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय से ही उन्होंने भाजपा को मज़बूत बनाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। 'श्रीराम जन्मभूमि' आंदोलन में भी उनकी महती भूमिका के लिए उन्हें यह देश हमेशा याद रखेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और मेरे लिए तो यह बहुत ही पीड़ादायक क्षण है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री कल्याण सिंह उ.प्र. ही नहीं भारतीय राजनीति की वह क़द्दावर हस्ती थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से देश और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका लम्बा राजनीतिक जीवन जनता-जनार्दन की सेवा में समर्पित रहा। वे उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए।

राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता व जन सेवा के पर्याय थे कल्याण सिंह: योगी आदित्यनाथ

श्री कल्याण सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनेक ट्वीट कर कहा कि भारतीय राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता व जन सेवा के पर्याय, अप्रतिम संगठनकर्ता एवं लोकप्रिय जननेता आदरणीय कल्याण सिंहजी का देहावसान संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है।

उन्होंने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंहजी को एक राजनीतिक संत कहूं, जिसे पद-प्रतिष्ठा का मोह छू तक न गया हो अथवा दृढ़ संकल्प के प्रतिमूर्ति मानूं, जो लक्ष्य का संधान होने तक अर्जुन की भांति एकनिष्ठ भाव के साथ प्रयत्नशील रहे और अंततः सफलता ने उनका वरण किया...दिवंगत पुण्यात्मा को मेरी शब्दांजलि।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिजनों को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। समाज, कल्याण सिंह जी को उनके युगांतरकारी निर्णयों, कर्तव्यनिष्ठा व शुचितापूर्ण जीवन के लिए सदियों तक स्मरण करते हुए प्रेरित होता रहेगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को बुलंदशहर जिले के नरोरा गंगा तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। श्री सिंह के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश एवं देश के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैप नीति के तहत वाहन स्क्रैप के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

आज वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ हुआ, जिसे भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा जा सकता है। वाहन स्क्रैप नीति अनुपयुक्त और प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को चरणबद्ध व पर्यावरण अनुकूल तरीके से हटाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम से पहले ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि हमारा उद्देश्य एक व्यावहारिक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाना है और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहते हुए सभी हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन करना है।

राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस नीति से नये भारत में वाहन सेक्टर और आवागमन सुविधा को नई पहचान मिलेगी। यह नीति देश में वाहनों की तादाद के आधुनिकीकरण में बड़ी भूमिका निभायेगी। इसके कारण अनुपयुक्त वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आवागमन सुविधा में आधुनिकता लाने से न केवल यात्रा और यातायात का बोझ कम होता है, बल्कि वह आर्थिक विकास में सहायक भी सिद्ध होती है। इक्कीसवीं सदी के भारत का लक्ष्य है स्वच्छ, दबाव-मुक्त तथा सुविधाजनक आवागमन और यही समय की मांग भी है।

श्री मोदी ने कहा कि नई स्क्रैप नीति चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट से धन निर्माण में परिवर्तित करने वाले अभियान के साथ जुड़ी है। इस नीति से देश के शहरों से प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण को सुरक्षित बनाने और तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता भी जाहिर होती है। यह नीति 'री-यूज, री-साइकिल, रिकवर' के सिद्धांत का पालन करती है और यह वाहन सेक्टर व धातु सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने को भी प्रोत्साहन देगी। यह नीति 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों नौकरियां पैदा होंगी।

उन्होंने कहा कि इस नीति से आम जनता को हर तरह से बहुत लाभ होगा। पहला लाभ यह होगा कि पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर प्रमाणपत्र दिया जाएगा। जिन लोगों के पास यह प्रमाणपत्र होगा उन्हें नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उन्हें सड़क कर में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि इसमें पुराने वाहन के रख-रखाव के खर्च, मरम्मत के खर्च और ईंधन की कुशलता की भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधे तौर पर जीवन से जुड़ा है। पुराने वाहनों और पुरानी तकनीक की वजह से होने वाले सड़क हादसों में कुछ राहत मिलेगी। चौथा लाभ यह होगा कि यह हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करेगी।

श्री मोदी ने आखिर में कहा कि आज का भारत अपने नागरिकों को वैश्विक मानक सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यही सोच बीएस-4 से बीएस-6 की तरफ बढ़ने की वजह है। ■

जम्मू-कश्मीर में भाजपा नेता शहीद

आतंकवादियों ने 17 अगस्त को भाजपा कार्यकर्ता और होम शाली बाग विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री जावेद अहमद डार को शहीद कर दिया। जावेद अहमद डार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बज़लू जागीर गांव में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "आज हमने कायरतापूर्ण हमले में जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में भाजपा नेता जावेद अहमद डार को खो दिया। भाजपा नेताओं को लगातार निशाना बनाने से हम जम्मू-कश्मीर के विकास और शांति के एजेंडे से विचलित नहीं होंगे। मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरी पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है।"

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर ने 11 अगस्त को कुलगांव में शहीद भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी। डार पर आतंकियों का हमला एक महीने में भाजपा नेता पर तीसरा हमला है। 13 अगस्त को जम्मू के राजौरी जिले में भाजपा नेता श्री जसबीर सिंह के घर पर आतंकवादियों ने उस समय ग्रेनेड फेंका, जब वह और उनके भाई श्री बलबीर सिंह का परिवार घर की दीर्घा में बैठे थे, जिसमें दोनों परिवारों के सात सदस्य घायल हो गए। बाद में भाजपा नेता के चार वर्षीय भतीजे का सरकारी कॉलेज राजौरी में देहांत हो गया।

गुलाम रसूल डार

जावेद अहमद डार

इससे पहले 9 अगस्त को अनंतनाग में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष व सरपंच श्री गुलाम रसूल डार व उनकी पत्नी श्रीमती जवाहीरा बेगम शहीद हो गए थे। आतंकी श्री जावेद अहमद डार के घर में जबरन घुस गए और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस आतंकी घटना में उन्हें गोली लगने से गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही देहांत हो गया। ■

टीकाकरण का नया इतिहास

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

सात अगस्त, 2021 को भारत ने कोरोना को परास्त करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 50 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला टीकाकरण कार्यक्रम है। तमाम अवरोधों के बावजूद यह उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, कोरोना वॉरियर्स के लगन और वैज्ञानिकों व उद्यमियों के साहसिक प्रयास का परिचायक है। आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत ने इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कैसे की?

यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा था कि देश में केवल नौ महीने में एक नहीं, बल्कि दो-दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन बनकर तैयार हुई और वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग शुरू हुआ। इतने विशाल देश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 16 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देश को टीकाकरण में पहले 10 करोड़ का आंकड़ा छूने में 85 दिन लगे थे, लेकिन इसके बाद इसमें तेजी आती गई। अनिवार्य लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान की गई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ-साथ स्पूतनिक का भी देश में उत्पादन शुरू हुआ। इसी 7 अगस्त को जॉनसन ऐंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री लगातार निगरानी करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि 10 करोड़ से 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने में भारत को महज 45 दिन लगे। इसी तरह 20 से 30 करोड़ तक पहुंचने में सिर्फ 29 दिन, 30 से 40 करोड़ तक पहुंचने में 24 दिन और 40 करोड़ से 50 करोड़ वैक्सीन डोज में सिर्फ 20 दिन लगे। यह आंकड़ा निस्संदेह मील का पत्थर है, लेकिन हम इस गति को बनाए रखेंगे और इस वर्ष के अंत तक हरेक देशवासी को वैक्सीनेट करने में सफल होंगे।

इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस साल के अंत तक हमारे पास लगभग 136 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगे। अगस्त में लगभग 25.65 करोड़, सितंबर में 26.15 करोड़, अक्तूबर में कुल 28.25 करोड़, नवंबर में 28.25 करोड़ और दिसंबर में 28.5 करोड़ खुराक का उत्पादन होने वाला है। अन्य वैक्सीन को मान्यता देने की प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है।

एक ओर, प्रधानमंत्री देश के 135 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए दिन-रात काम कर रहे थे, टीकाकरण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे थे, वहीं विपक्ष नकारात्मकता फैलाने में लगा था और दुष्प्रचार के जरिए जनता को गुमराह कर रहा था। कभी वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया, तो कभी इसके साइड इफेक्ट को लेकर दुष्प्रचार किया गया। देशवासियों को गिनी पिग्स, लैब रैट्स और न जाने क्या-क्या कहा गया?

संसद के मौजूदा मानसून सत्र में जब प्रधानमंत्री ने कोविड और वैक्सीनेशन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, तब कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी के नेता इस बैठक में आए ही नहीं। इससे पहले भी जब-जब वैक्सीन को लेकर बैठक बुलाई गई, तो कभी छत्तीसगढ़ और बंगाल की मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होते, तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रणनीतिक बैठक को सार्वजनिक कर देते हैं। कभी झारखंड के मुख्यमंत्री बैठक को लेकर बयान देते हैं, तो कभी पंजाब और राजस्थान की कांग्रेसी सरकारों का अनर्गल प्रलाप होने लगता है। यही अपने आप में कहने के लिए काफी है कि विपक्ष ने किस तरह भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को पटरी से उतारने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने देश के कोरोना वॉरियर्स की लगातार हौसला अफजाई की। उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और 'मेरा बूथ-कोरोना मुक्त' अभियान भी सफल होगा। अब तक इस अभियान के तहत लगभग डेढ़ लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान हमारे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने मानवता की जो सेवा की है, उसे शब्दों में

बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसी कई कहानियां हैं, जब हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। कई महिला डॉक्टरों व नर्सों ने मानवता की सेवा के लिए अपनी ममता की कोख को भी दांव पर लगा दिया। कई तो महीनों अपने परिवार से नहीं मिल पाए। उनके लिए मरीजों की बेहतरी ही लक्ष्य बन गया। कोरोना से मुक्त होने के बाद जब मरीजों के चेहरे पर मुस्कान खिलती, तो उनमें उन्हें आत्मसंतोष मिलता था। ऐसे सभी डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों एवं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को मैं नमन करता हूं। उन्होंने हर देशवासी में यह जज्बा भरा कि चुनौती कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर देशवासी ठान लें, तो हर चुनौती को परास्त किया जा सकता है।

हम सब जानते हैं कि पहले टीका भारत आने में कितने-कितने साल लग जाते थे। देश में जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन आने में वर्षों लग गए थे। इसी तरह, पोलियो और टिटनेस की वैक्सीन दुनिया में आने के कई साल बाद भारत आ पाई थी। विदेश में टीके का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में टीके का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। इस बार दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि जो भारत वैक्सीन के लिए दुनिया के अन्य देशों पर आश्रित रहा करता था, उसने कैसे न केवल विश्वस्तरीय वैक्सीन विकसित की, बल्कि इस कार्यक्रम को देश में सफलतापूर्वक लागू भी किया, बल्कि संकट के समय दुनिया के अन्य देशों की मदद भी की। आज से पहले भारत के बारे में शायद ऐसी कल्पना भी न की जा सकती थी। यह हमारे नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जो हरेक भारतवासी के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। हम न रुकेंगे, न थकेंगे और इसी जज्बे व लगन के साथ टीकाकरण को गति देंगे। हम इस वर्ष के अंत तक देश के हर नागरिक के टीकाकरण के लक्ष्य को साकार करने में जरूर सफल होंगे। ■

जायडस कैडिला द्वारा विकसित 'जाइकोव-डी' को आपातकालीन उपयोग के लिए मिली मंजूरी

'मिशन कोविड सुरक्षा' के तहत डीबीटी-बीआईआरएसी के साथ साझेदारी में दुनिया का पहला कोविड-19 डीएनए टीका विकसित

'जाइकोव-डी' के लिए जायडस कैडिला को 20 अगस्त, 2021 को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) से आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी (ईयूए) मिल गई। यह दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 टीका है। इसका उपयोग बच्चों के साथ-साथ 12 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए किया जा सकता है।

'मिशन कोविड सुरक्षा' के तहत भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में विकसित और बीआईआरएसी द्वारा कार्यान्वित जाइकोव-डी को क्लीनिकल पूर्व अध्ययन और पहले एवं दूसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण के लिए नेशनल बायोफार्मा मिशन के जरिये और तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण के लिए मिशन कोविड सुरक्षा के जरिये कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टिया के तहत समर्थन दिया गया है।

तीन खुराक वाला यह टीका लगाए जाने पर शरीर में सार्स-सीओवी-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हासिल करता है जो बीमारी से सुरक्षा के साथ-साथ वायरस को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लग-एंड-प्ले तकनीक जिस पर प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म आधारित है, को वायरस में म्यूटेशन से निपटने के लिए आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है जैसाकि पहले से ही हो रहा है।

इस टीके का तीसरे चरण का क्लीनिकल परीक्षण 28,000 से अधिक लोगों पर किया गया। इसमें लक्षण वाले आरटी-पीसीआर पॉजिटिव मामलों में 66.6 प्रतिशत प्राथमिक प्रभावकारिता दिखी। यह कोविड-19 के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टीका परीक्षण है। यह टीका पहले और दूसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण में प्रतिरक्षण क्षमता और सहनशीलता और सुरक्षा प्रोफाइल के मोर्चे पर जबरदस्त प्रदर्शन पहले ही कर चुका है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण की निगरानी एक स्वतंत्र डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड (डीएसएमबी) द्वारा की गई है।

'जाइकोव-डी' वैक्सीन को मंजूरी मिलना भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अगस्त को कहा कि जाइडस यूनिवर्स की दुनिया की पहली डीएनए आधारित 'जाइकोव-डी' वैक्सीन को मंजूरी मिलना भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। सीडीएससीओ इंडिया इनफो के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे जोश के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। जाइडस यूनिवर्स की दुनिया की पहली डीएनए आधारित 'जाइकोव-डी' वैक्सीन को मंजूरी मिलना भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ■

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियानः एक अनुकरणीय पहल

शिवप्रकाश
राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन), भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी का आह्वान किया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने योग्य समाज को तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक ग्राम में 2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करेगी। स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के इस अभियान का लक्ष्य निर्धारित करते समय भाजपा नेतृत्व ने कहा कि हम 2 लाख गांवों में 4 लाख युवक एवं युवतियां का प्रशिक्षण करेंगे।

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का चतुर्दिक विस्तार हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि भाजपा की इतनी बड़ी शक्ति केवल चुनाव लड़ने तक सीमित रहे, अथवा देश के सम्मुख चुनौतियों का मुकाबला करने में भी उसका योगदान होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर भाजपा सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम अब भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वभाव ही बन गया है।

कोरोना महामारी के कालखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'Feed The Needy' अभियान के अंतर्गत भोजन, मास्क, सैनिटाइजर, वृद्धों को औषधि, बच्चों को दूध आदि पहुंचाकर अपनी संवेदना एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का नित निर्वहन किया है। कोरोना की दूसरी लहर में सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत पुनः राशन वितरण, रक्तदान एवं कोरोना रोकथाम के लिए जागरूकता के कार्यक्रमों को व्यवहार रूप दिया है। जब लोग मृत्यु के भय से अपने मृतकों के शव को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे तब भाजपा कार्यकर्ता मृतकों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। जहां देश के अन्य दल कोरोना के कारण आइसोलेशन में चले गए अथवा मोदी सरकार की आधारहीन आलोचना करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, वहीं भाजपा देश के दुःख-दर्द में साथ खड़ी नजर आई। यह भाजपा की समाज के प्रति संवेदनशीलता का ही प्रकटीकरण है।

देशभर में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला करके अभियान का श्रीगणेश किया, जिसका उद्घाटन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने बताया कि यह किसी राजनैतिक पार्टी का यह सबसे बड़ा अभियान होगा। देश के सभी प्रदेशों की कार्यशाला अगस्त तक संपन्न होगी।

मंडल की कार्यशालाओं में प्रत्येक बूथ एवं ग्राम तक के एक युवक एवं एक युवती– 2-2 वालंटियर उपस्थित होंगे।

कोरोना प्रतिरोधक व्यवहार, कोरोना होने पर क्या-क्या करें, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय आदि विषयों के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए योगासन, प्राणायाम, दिनचर्या, खान-पान एवं आयुर्वेदिक उपचार आदि सभी वालंटियर प्रशिक्षण के विषय हैं।

समाज में चलने वाली अनेक सामाजिक संस्थाएं, सेवाभावी व्यक्ति आदि भी इस अभियान में सहायक बनें, इसका भी प्रयास हो रहा है। अभियान की शुचितापूर्ण भावना के कारण समाज में चिकित्सकों का जुड़ाव भी व्यापक मात्रा में हो रहा है। आवश्यक कोरोना किट प्रत्येक गांव के वालंटियर को देने की व्यवस्था भी हो रही है। अभियान के प्रति समाज में स्वीकृति एवं उत्साह के कारण लगता है कि अभियान में वालंटियर की संख्या 4 लाख से कहीं अधिक होगी। अनेक प्रदेश ग्राम से भी आगे जाकर बूथ तक कार्य-विस्तार का प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास नेतृत्व के मार्गदर्शन एवं समाज के सहयोग से यशस्वी होगा। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तब समाज का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। देश श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में एवं श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में कोरोना को पराजित करने में सफल होगा।

'कोरोना हारेगा, देश जीतेगा' के संकल्प के साथ हम सभी इस अभियान के सहभागी बनें। ■

आज देशभर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अगस्त को 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रमोट किए गए महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्यों/सामुदायिक संसाधन सदस्यों के साथ संवाद किया।

श्री मोदी ने 4 लाख से भी अधिक एसएचजी को 1,625 करोड़ रुपये की पूंजीकरण सहायता राशि भी जारी की। इसके अलावा उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमएफएमई (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकरण) योजना के तहत 7,500 एसएचजी सदस्यों के लिए सीड मनी के रूप में 25 करोड़ रुपये और मिशन के तहत प्रमोट किए जा रहे 75 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को फंड के रूप में 4.13 करोड़ रुपये जारी किए।

श्री मोदी ने कोरोना काल में अभूतपूर्व सेवाओं के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मास्क एवं सैनिटाइजर बनाने और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने तथा जागरूकता फैलाने में उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित किया।

श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं में उद्यमिता का दायरा बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी और अधिक भागीदारी के लिए रक्षा बंधन की पूर्व संध्या पर आज 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को एक बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और दीनदयाल अंत्योदय योजना से ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों का यह आंदोलन तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देशभर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जो 6-7 वर्षों के आंकड़े से तीन गुना अधिक है।

स्वयं सहायता समूहों और दीनदयाल अंत्योदय योजना से ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति आई है। आज देशभर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जो 6-7 वर्षों के आंकड़े से तीन गुना अधिक है

श्री मोदी ने इस सरकार से पहले के समय को याद किया जब करोड़ों बहनों के पास बैंक खाता नहीं होता था और वे बैंकिंग प्रणाली से कोसों दूर थीं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से इस सरकार ने जन धन खाते खोलने का व्यापक अभियान शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा कि आज 42 करोड़ से अधिक जन धन खाते हैं, जिनमें से करीब 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्ज लेना आसान बनाने के लिए ये बैंक खाते खोले गए।

श्री मोदी ने कहा कि कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एक विशेष फंड बनाया गया है। स्वयं सहायता समूह भी इस फंड से मदद लेकर कृषि आधारित सुविधाओं का निर्माण कर सकेंगे। स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं उचित दर निर्धारित करके इन सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं और दूसरों को किराए पर भी दे सकती हैं।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार मेड इन इंडिया खिलौनों को भी बढ़ावा दे रही है और इसके लिए हर संभव मदद भी कर रही है। खास तौर से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें इस हुनर से परंपरागत रूप से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूहों के लिए काफी संभावनाएं हैं।

श्री मोदी ने कहा कि सभी बहनों को घर, शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार बहनों-बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ महिलाओं का सम्मान बढ़ा है बल्कि बेटियों-बहनों का भी आत्मविश्वास बढ़ा है।

श्री मोदी ने स्वयं सहायता समूहों से राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को अमृत महोत्सव से भी जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ से अधिक बहन-बेटियों की सामूहिक शक्ति से अमृत महोत्सव को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकेगा। श्री मोदी ने महिलाओं से कहा कि वह यह सोचे कि इसके लिए वे सेवा भावना के साथ कैसे सहयोग कर सकती हैं। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए पोषण संबंधी जागरूकता अभियान, कोविड-19 के टीके लगाने, गांवों में स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे चलाए जा रहे अभियानों का भी उदाहरण दिया।

प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की सराहना की और कहा अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत उनके प्रयासों से हर जगह फैलेगा और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। ■

मोदी सरकार समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है: के. लक्ष्मण

भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण का कहना है कि मोदी सरकार की योजनाओं से बड़े पैमाने पर पिछड़ा वर्ग समुदाय लाभान्वित हुआ है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को मतदाता के रूप में देखा है और उन्हें कभी महत्व नहीं दिया। पिछले दिनों डॉ. लक्ष्मण से कमल संदेश के सह संपादक संजीव कुमार सिन्हा एवं रामप्रसाद त्रिपाठी ने बातचीत की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश-

मोदी सरकार ने हाल ही में मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लिया। कृपया इस संबंध में हमें बताएं?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को 27 प्रतिशत तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लिया। इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ही लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे।

इस निर्णय के क्या दूरगामी परिणाम होंगे?

प्रधानमंत्री श्री मोदी हमारे प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत अंत्योदय सिद्धांत के आधार पर सरकार चला रहे हैं। मोदी सरकार समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज अनुसूचित जाति समाज से देश के राष्ट्रपति बने हैं तो पिछड़ा वर्ग से देश के प्रधानमंत्री। पूरे देश में ओबीसी आबादी 50 प्रतिशत है। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय से निस्संदेह पिछड़ा वर्ग सशक्त होगा। मोदीजी द्वारा प्रस्तुत 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास' इस ध्येय से संपूर्ण देशवासियों का हित संवर्धन होगा।

कांग्रेस ने इस निर्णय को चुनावी एजेंडा करार दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर?

सिर्फ राजनीति के लिए हम निर्णय नहीं लेते हैं, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। हम जो बोलते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो बोलते हैं। धारा 370 हटाने, राममंदिर का निर्माण, तीन तलाक खत्म करने, ऐसे अनेक निर्णय हुए हैं। जो वंचित हैं, पार्टी और सरकार सभी जगह, हम उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस क्यों पिछड़ा वर्ग को केवल मतदाता के नाते देखती रही है, इंसानियत के नाते क्यों नहीं देखा? पिछड़ा वर्ग हित में विभिन्न आयोगों ने सिफारिशें कीं, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस को तो हक ही नहीं है सवाल पूछने का।

हाल ही में मंत्रिपरिषद् विस्तार में समाज के सभी वर्गों से मंत्रियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। इसे आप किस रूप में देखते हैं?

वर्तमान में मोदी सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं जबकि 12 अनुसूचित जाति एवं 8 अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। 11 महिला मंत्री भी सरकार में शामिल हैं। भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए मंत्रिपरिषद् में उन्हें शामिल कर सम्मान दिया गया है। मोदी सरकार सही मायने में सामाजिक न्याय पर अमल कर रही है। हम देश भर में इन मंत्रियों के जन-समर्थन को लेकर 'जन आशीर्वाद यात्रा' कर रहे हैं।

मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के हित में और कौन से कदम उठाए हैं?

मोदी सरकार ने गत सात वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह ऐतिहासिक कदम था। पहली बार केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों, सैनिक स्कूलों में भी आरक्षण लागू किया जा रहा है, जिससे इस साल पिछड़ा वर्ग के लगभग 70

हजार छात्रों को लाभ होनेवाला है। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया। क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पहली बार आरक्षण पर अमल किया जा रहा है। 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद किसी सरकार ने पिछड़ा वर्ग पर इतना ध्यान नहीं दिया, जितना कि मोदी सरकार दे रही है।

आजादी के बाद 75 वर्षों में तो लगभग 60 वर्ष कांग्रेस सरकार में थी। इसमें भी लगभग 35 साल एक ही परिवार ने राज किया। पचास के दशक में नेहरूजी जब प्रधानमंत्री थे, तब काका कालेलकर आयोग ने जो सिफारिशें की, उस पर संसद में चर्चा नहीं की और उसकी अनदेखी की। इंदिरा गांधीजी 17 साल प्रधानमंत्री रहीं, इन्होंने काका कालेलकर आयोग को कोई महत्व नहीं दिया और न ही कोई अन्य आयोग बिठाया। कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया। जब कभी आरक्षण का मुद्दा आया, उसने समर्थन नहीं किया।

जनता पार्टी शासन में मोरारजीभाई प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयीजी, लालकृष्ण आडवाणीजी उस सरकार में मंत्री थे, तभी मंडल आयोग का गठन हुआ। इसकी सिफारिशें भी तब हुईं जब केंद्र में वीपी सिंह सरकार आई। वीपी सिंह सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया। राजीव गांधीजी ने दो बार लगातार विपक्ष के नेता के नाते इसके खिलाफ बोला। इतना ही नहीं, 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी। क्षेत्रीय दल– समाजवादी, राजद, बसपा आदि जो अपने को पिछड़ा वर्ग के हितैषी के रूप में प्रस्तुत करते नहीं थकते हैं, उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बारे में सोचा?

- **मेडिकल शिक्षा में ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे**
- **मोदी सरकार सही मायने में सामाजिक न्याय पर अमल कर रही है**
- **राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह ऐतिहासिक कदम था**
- **मोदी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उससे पिछड़े और गरीबों को बहुत लाभ हो रहा है**
- **ओबीसी मोर्चा मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक घर-घर दस्तक देगा और जन-जन को जागृत करेगा**

जब मोदी सरकार द्वारा 2017 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया, वामपंथी दलों ने विरोध किया। लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। राज्यसभा में यह बिल आने पर कांग्रेस ने फिर इसका विरोध किया। श्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में समिति बनी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, श्री अमित शाहजी एवं श्री जगत प्रकाश नड्डा की पहल से राज्यसभा में दोबारा इसे पारित किया गया। भाजपा शासित अनेक राज्यों में ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री बने हैं।

सिर्फ आरक्षण की ही बात नहीं, मोदी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उससे पिछड़े और गरीबों को बहुत लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि से सबसे बड़े पैमाने पर लाभान्वित पिछड़ा वर्ग समाज ही हुआ है। इसलिए यह गरीबों-किसानों की सरकार है। शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित; इन वर्गों की सरकार है। इन वर्गों के हित में काम करनेवाली सरकार है, युवाओं, महिलाओं की भी इसमें भागीदारी है।

भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस दौरान मोर्चा की क्या सक्रियता रही?

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी के अंदर पिछड़ा वर्ग समुदाय को काफी महत्व दिया जा रहा है। इस समुदाय से अनेक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मेरे द्वारा संभालने के बाद अनेक कार्यक्रम हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है। चार बार राष्ट्रीय परिषद् की बैठकें हुई हैं। पहली बार मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई। संसद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा नए मंत्रियों का परिचय कराने के समय विरोध किया और ऐसा नहीं करने दिया। भाजपा ने तय किया कि आम आदमी के बीच नए मंत्रियों का अभिनंदन समारोह करेंगे। मोर्चा द्वारा मोदी सरकार में ओबीसी समुदाय के 27 मंत्रियों का अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। पूर्व के दोनों कार्यक्रमों में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। आज देश भर में हम संगठन मजबूत करने के लिए प्रवास कर रहे हैं। 28 प्रदेशों में कार्यसमिति गठित हुई है। लगभग 801 जिलों में ओबीसी मोर्चा का गठन हुआ है। लगभग 9507 मंडलों में पहली बार ओबीसी मोर्चा समिति गठित हुई है।

भाजपा ओबीसी मोर्चा की आगामी क्या योजनाएं हैं?

हम हर प्रदेश में सामाजिक कल्याण सम्मेलन करेंगे। जहां-जहां पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बिठाया गया, उसको संवैधानिक दर्जा देने की मांग भी हमारी है, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे। ओबीसी समुदाय में भाजपा की विचारधारा का प्रचार करेंगे और उन्हें मोर्चा से जोड़ेंगे। अन्य दलों द्वारा ओबीसी समुदाय को किस तरह धोखा दिया गया है, इसका पर्दाफाश करेंगे। ओबीसी मोर्चा मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक घर-घर दस्तक देगा, गांव-गांव पहुंचेगा और जन-जन को जागृत करेगा। पिछड़ा वर्ग का समर्थन लेने में भाजपा ओबीसी मोर्चा सक्रिय रूप से काम करेगा। ■

सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

'आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करते हुए देश प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है'

गत 20 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ, गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने (जूना) सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर श्री लालकृष्ण आडवाणी, केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री एवं गुजरात के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री उपस्थित थे।

दुनिया भर के श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए श्री मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिये अदम्य इच्छाशक्ति दिखाई थी। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75वें वर्ष में सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता प्रदान करने में सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हर कालखंड की यह मांग रही है कि हम धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को खोजें और लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें।

प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि मंदिर को बार-बार तोड़ा गया, लेकिन हर हमले के बाद वह कैसे फिर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि यह इस विश्वास का प्रतीक है कि असत्य कभी सत्य को पराजित नहीं कर सकता और आतंक कभी आस्था को कुचल नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वह किसी कालखंड में कुछ समय के लिये भले हावी हो जाये, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता, वह ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। यह उस समय भी सत्य था, जब कुछ आक्रमणकारी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ रहे थे और आज भी उतना ही सत्य है, जब ऐसी सोच दुनिया के सामने खतरा बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि हमारे लिए इतिहास और धर्म का सार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है।

उन्होंने कहा कि देश आधुनिक अवसंरचना का निर्माण कर प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

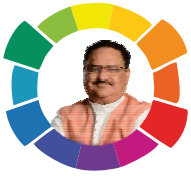

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि 'सदैव अटल' पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने जा रहे भारतीय पैरा–एथलीट दल के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये 'समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता' पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' के दौरान 4 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को 1,625 करोड़ रुपये की पूंजीकरण सहायता राशि जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh @KamalSandesh

kamal.sandesh KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**

36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23

Licence to Post without Prepayment

Licence No. U(S)-41/2021-23

नई दिल्ली में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

छायाकार: अजय कुमार सिंह